सत्ता" में प्रकाशित सेन्ट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ से संबंधित समाचार का ओर दिलाया गया है जिसमें वहां व्याप्त अनियमितताओं का ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज पाटिल): (क) जी, नहीं। केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान (सीडीआरई), लखनऊ के बारे में कोई समाचार दिनांक 16 दिसम्बर, 1985 के "जनसत्ता" हिन्दी दैनिक में प्रकाशित नहीं हुआ था। फिर भी, दिनांक 17 दिसम्बर, 1985 के "जनसत्ता" हिन्दी दैनिक "सरकारी संस्थान से हीरोईन तस्करी" शीर्षक से एक समाचार छपा था। उसके अगले दिन (18-12-85) को निदेशक, सीडीआरई ने सम्पादक "जनसत्ता" को पत्र लिखकर इन आरोपों का खण्डन किया था। दिनांक 24 दिसम्बर, 1985 के हिन्दी दैनिक संस्करण में निदेशक, सीडीआरई द्वारा प्रेषित खण्डन प्रकाशित किया गया था।

(ख) निदेशक, सीडीआरई से समाचार में प्रकाशित आरोपों की जांच करने के लिए और अपनी सम्मति भेजने के लिए कहा गया है।

Indian scientists serving abroad

1791. DR. MOHD. HASHIM KIDWAI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state the number of Indian scientists who were serving abroad as in December, 1985?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND IN THE DEPARTMENT OF OCEAN DEVELOPMENT, ATOMIC ENERGY ELECTRONICS AND SPACE (SHRI SHIVRAJ PATIL): No precise information is available regarding the number of Indian scientists and technologists abroad. However the Council of Scientific & Industrial Research maintains an Indians Abroad Register for enrolling persons engaged in study, training, research, employment abroad. The registration is voluntary and as on 31-12-1985 the number of Indian scientists, technologists, engineers and medical personnel registered under the scheme was 24019. Out of them 11446 have reported their return to India.

Manufacture of cheap colour TV sets

1792. SHRI SANTOSH KUMAR SAHU: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government propose to manufacture cheap colour T.V. sets in the country; and

(b) if so, what is the proposed annual capacity and by when these sets will be made available?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND IN THE DEPARTMENT OF OCEAN DEVELOPMENT, ATOMIC ENERGY, ELECTRONICS AND SPACE (SHRI SHIVRAJ PATIL): (a) and (b) Government have no proposal to manufacture cheap colour T.V. sets. However, Electronics Trade & Technology Development Corporation Limited (ET&T), a public sector undertaking, of the Department of Electronics, has launched a Material, Technology and Brand Name (MTB) programme, which is designed to provide comprehensive service package for 36 cm.

B&W and 51 cm CTV sets, comprising

— supply of material package;

— supply of technology for conversion of the material into a cost effective product

— publicity with "ET&T" as a technology brand name.

The purpose of the MTB programme is to provide good quality, cheaper CTV sets to consumers.

It is expected that by 31-3-1986, in addition to about 1200 Nos. of CTV sets already sold under the MTB programme, 3000 Nos. of CTV sets may be ready for marketing. During 1986-87, it is expected that CTV sets to be manufactured under the programme may be around 10,000 Nos. per month, on an average.

केन्द्रीय सरकार और राज्यों के बीच पत्राचार

1793. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकारों के साथ किस भाषा में पत्राचार करती है; और

(ख) क्या यह सच है कि इन राज्य सरकारों को बाध्य होकर केन्द्र सरकार के साथ अंग्रेजी में पत्राचार करना पड़ता है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) राजभाषा अधिनियम, 1963 के अंतर्गत बनाये गये राजभाषा नियम, 1976 के नियम 3 के अनुसार केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से उत्तर प्रदेश बिहार, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों को पत्रादि असाधारण दशाओं को छोड़कर हिन्दी में होंगे और यदि उनमें से किसी को कोई पत्रादि अंग्रेजी में भेजे जाते हैं तो उनके साथ उनका हिन्दी अनुवाद भी भेजा जाएगा

(ख) जी नहीं, केन्द्र सरकार द्वारा इन राज्य सरकारों को पत्रादि केवल अंग्रेजी में भेजने के लिए कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं।

Plan outlay for Maharashtra for 1986-87

1794. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the details of annual plan for Maharashtra for 1986-87 as approved by the Planning Commission;

(b) what is the amount demanded by the Maharashtra Government for the annual plan and approved by the Planning Commission;

(c) whether any priority in the annual plan of the State was given for the development of Vidharba; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI AJIT PANJA): (a) and (b) A statement is enclosed (*See* below).

(c) and (d) Yes, Sir. Priority is being given for development of Vidharbha. In addition to the investments taking place in Vidharba through the normal plan programmes, Rs. 537.32 crores have been allocated